भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 395

19 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

तमिलनाडु में मेट्रो रेल परियोजनाओं का विस्तार

†*395. श्री जी. सेल्वमः

श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विस्तार से शहरी आवागमन में सुधार, यात्रा के समय में कमी, वाहनों से उत्सर्जन के स्तर में गिरावट और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में चल रहे और प्रस्तावित मेट्रो विस्तार के परिणामस्वरूप यात्रियों की संख्या में अनुमानित वृद्धि, यातायात में कमी के लाभों और कार्बन उत्सर्जन में कटौती का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने टियर-।। शहरों के तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बढ़ते औद्योगिक आधार और यातायात घनत्व में वृद्धि को देखते हुए वहां मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है या उन पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तमिलनाडु में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए स्वीकृत तथा जारी की गई और उपयोग में लाई गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मेट्रो प्रणालियों को समय पर पूरा करने, लागत दक्षता सुनिश्चित करने और मेट्रो प्रणाली को सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

विवरण

श्री सेल्वम जी और श्री सी एन अन्नादुरई द्वारा तमिलनाडु में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विस्तार के संबंध में दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *395 (15वां स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) शहरी परिवहन, जो शहरी विकास का एक अभिन्न अंग है, राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर को शुरू करने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर, प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, शहरों अथवा शहरी समूहों में ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है। अतीत में, केंद्र सरकार ने चेन्नई चरण-1 और चरण-1 विस्तार के तहत 54 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के लिए वित्तीय सहायता दी थी, जो क्रमशः फरवरी 2019 और मार्च 2022 से चालू हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 63,246.4 करोड़ रुपये की लागत से 118.9 किलोमीटर की लंबाई वाले चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण-2 को स्वीकृति दी है।

मौजूदा मेट्रो नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए इस तरह के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अध्ययन के हिस्से के रूप में सवारियों और इनकी संख्या में वृद्धि, यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लाभ और कार्बन उत्सर्जन में कमी का आकलन किया जाता है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने सूचित किया है कि चेन्नई मेट्रो चरण 1 और चरण-1 विस्तार की वर्तमान दैनिक सवारियों की संख्या 4.6 लाख है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने यह भी सूचित किया है कि चेन्नई मेट्रो चरण-1 और चरण-1 के विस्तार के कार्यान्वयन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 2,29,357 टन की कमी आई है। चेन्नई मेट्रो चरण-2 के चालू होने पर दैनिक सवारियों की अनुमानित वृद्धि 17.7 लाख है।

(घ) स्वीकृति आदेश के अनुसार, चेन्नई मेट्रो रेल चरण-2 परियोजना के लिए भारत सरकार का कुल अंशदान इक्विटी और अधीनस्थ ऋण के रूप में 7,424.9 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार बाह्य ऋण के लिए पास थ्रू सहायता भी प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में परियोजना स्वीकृत होने के बाद से चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा समय-समय पर दी गई मांग के अनुसार चेन्नई मेट्रो चरण-2 परियोजना के लिए 14,242.64 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है।

जारी की गई धनराशि का वर्षवार विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

(करोड़ रुपए में)

जारी की गई निधि (वर्षवार)	इक्विटी	अधीनस्थ ऋण	पास थ्रू सहायता	कुल
2024-25	3,566.21	537.82	1,450.12	5,554.15
2025-26	1,841.19	458.81	6,388.49	8,688.49
कुल जारी	5,407.4	996.63	7,838.61	14,242.64

(ङ) चालू परियोजना की प्रगति की नियमित रूप से एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति, मेट्रो रेल निगम के निदेशक मंडल और केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जाती है ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सके। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने परियोजना की निगरानी और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) और भवन सूचना मॉडलिंग (बीआईएम) का कार्यान्वयन किया है। अनुबंध प्रबंधन के मुद्दों की आवधिक समीक्षा की जाती है और लागत दक्षता के लिए स्टेशनों, वायाडक्ट आदि के लिए डिजाइन को अनुरूपी बनाया गया है। सीएमआरएल ने आगे कहा है कि कॉरिडर को पहले से ही चेन्नई मेट्रो चरण 1 में प्रमुख बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के साथ-साथ चेन्नई मेट्रो चरण 2 जैसे अन्य परिवहन साधनों के साथ एकीकृत किया गया है।

*****